की मेंबर थी। इसकी जो ग्रांट्स कॉलेजों को मंजूर की गई, किसी को 7 करोड़, किसी को 8 करोड़, उसे दो साल हो गए, उसका आज तक एक भी पैसे का डिस्बर्समेंट पूरे देश में नहीं हुआ है। मैं चाहती हूं कि उसका डि-सेंट्रालाइजेशन हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): बहुत-बहुत धन्यवाद।

Recruitment Policy of Jammu and Kashmir Government

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं उन दुखी लोगों की आवाज एक बार फिर उठाना चाहता हूं, जो केवल इसलिए कि वे हिन्दू हैं, कश्मीर की घाटी से धकेलकर के बाहर निकाल दिए गए हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो जम्मू में या दिल्ली में और सारे देश भर में फैले हुए हैं जिनकी सेवाओं की, तकलीफों को अब तक सरकार आंख से ओझल करती रही है। मगर उसमें भी दुखद् स्थिति यह है कि ऐसे योग्य लोग जो कि सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनकी भी सेवा करने देने की स्थिति सरकार पैदा नहीं होने देना चाहती है। जहां हजारों लोग कैम्पों में सड़ रहे है, भिखारियों के रूप में आकर बसे हुए हैं, उन्हीं के परिवार में से यदि कोई नौजवान किसी सेवा के लिए एप्लाई करता है और वह योग्य पाया जाता है तथा उसका सलेक्शन भी हो जाता है लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती। कारण? उसको कहा जाता है कि — तुम, वैली में जाकर के नौकरी जोइन करो। जबकि सब जानते हैं कि वहां घाटी में जाकर कम से कम कोई हिन्दू वहां आराम से रह नहीं सकता। तो उसको नौकरी में सलेक्ट करने के बाद मजबूर करना कि वह वहां जाए, यह केवल एक प्रकार से अमानुषिक व्यवहार है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जरा यह देखे कि ऐसे भी कुछ लोग हैं विशेष संप्रदाय के जो कि वैली में अगर कहीं जाएं तो उन्हें वह तकलीफ नहीं होगी जो कि किसी हिन्दू परिवार के आदमी को होती है। इसलिए प्रथम तो यह चाहिए कि समानान्तर स्थिति में यदि यहां का नौजवान जो वहां जाकर बस नहीं सकता तथा उस क्षेत्र का दूसरा नौजवान वहां जाकर बस सकता है और आराम से रह सकता है तो उसको ही वहां पोस्टिंग दी जाए।

श्रीमन्, एक दूसरी स्थिति और विचित्र है। हमारे गृह मंत्री महोदय सुन रहे हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारी कर्मचारी हैं, वह ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में चले जाते हैं और उनकी हाजरी यहां पर दफ्तरों में मार्क की जाती है कि वे उपस्थित हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी, स्कूल के सरकारी अध्यापक जो पढ़ाते हैं वह पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं लेकिन वहां के मिले हुए वे अधिकारी उनकी प्रजेन्स अपने दफ्तर में, स्कूल में मार्क करते रहते हैं। एक तो वह लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर वापिस आकर नौकरी में काम करते हैं और दूसरी तरफ वह अभागा हिन्दू नौजवान है जो कि वहां परिवार से उखड़कर आया, यहां बसा, येनकेनप्रकारेण उन्होंने शिक्षा पूरी की, परीक्षा में बैठा, उत्तीर्ण हो गया, सलेक्ट हो गया लेकिन उसको कहा जाता है कि जाकर, वैली में जोइन करो, जबकि सब जानते हैं कि वह वहां जोइन नहीं कर सकता। तो सरकार को चाहिए कि अपना अमानवीय दृष्टिकोण विस्थापितों के बारे में बदलकर एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और जो लोग सलेक्ट हो जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर कहीं पर नियुक्त करे, जहां पर वास्तव में वह नौकरी कर सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Dr. Naunihal Singh. Dr. Sahib, You arc very expert in brevity.

Funding of Private Foreign Power Project by IDBI

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Thank you. Sir. On May 5, the House had discussed a Calling Attention Motion on 'Foreign Investment in Power Sector' and, in particular identified the Enron Company which is taking undue advantage of the liberalisation policy of the Government of India.

When another shocking news has come to the forefront, it is very urgent to bring it through you, Sir, to the notice of this august House. It is, perhaps, an irony that the State-owned Industrial Development Bank of India has been forced to agree to put in Rs. 1,500 crores in India's first private foreign power project of Enron's 2.8 billion dollars project. This is an irony which is heightened by the fact that the IDBI will not be participating in equity but will be funding virtually up to 75% of the project costs. Is this the entire idea of special incentives and sovereign guarantees